www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 भारत की नई बुलंद तस्वीर : 'झुकती है...

3 परंपरागत व गौरवपूर्ण ढंग से होगा स्वतंत्रता दिवस...

4 विधायक योगेन्द्र राणा के नेतृत्व में भव्य...

वर्ष: 9 | अंक: 289 | दिल्ली, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

जम्मू कश्मीर के कठुआ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद सोमवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि वह व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे एक समूह का हिस्सा था। अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 4 बजे हीरानगर सेक्टर में चंदवान और कोठे सीमा चौकियों के बीच सतर्क जवानों ने घुसपैठियों को देखा और उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों ने बार-बार दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अग्रिम चौकियों पर तैनात बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एक घुसपैठिया घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घायल घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

जबलपुर से गूंजेगी देशव्यापी डिजिटल क्रांति : सिंधिया

जबलपुर/भोपाल/नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में, मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह, जबलपुर के सांसद आशीष दुबे और टेलीकॉम सचिव नीरज मित्तल की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में भारत के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई। इस अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड के भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग और विश्व की चार अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों एरिक्सन, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, सिस्को एवं नोकिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

विपक्षी सांसदों ने 'वोट चोरी' के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक निकाला मार्च

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। वोट चोरी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, मैं शपथपत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं? यह उनका डाटा है, मेरा नहीं। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने सोमवार को कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बीच में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जब चुनाव आयोग द्वारा उनसे 'वोट चोरी' के आरोप पर शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने के अनुरोध के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं शपथपत्र पर हस्ताक्षर क्यों करूं? यह उनका डेटा है, मेरा नहीं। उन्हें इसे अपनी वेबसाइट से लेना चाहिए। वे बस ध्यान भटका रहे हैं। और किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल बंगलूरू में हुआ है; यह देश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। आज चुनाव आयोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। राहुल ने कहा, भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वे डरे हुए हैं। अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही। यह लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर दिखा दिया है, यह मल्टीपल मैन, मल्टीपल वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपना बहुत मुश्किल होगा।

कांग्रेस महासचिव और पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही है। वे हमें यहीं रोकना चाहते हैं। देश में कैसा लोकतंत्र है? सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आजादी नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 30 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कम से कम उन 30 लोगों को चुनाव आयोग कार्यालय तो जाने दो।'

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद के ठीक बाहर लोकतंत्र पर हमला और उसकी हत्या की जा रही है, क्योंकि विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने से रोक दिया गया। रमेश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव आयोग ही रहना चाहिए, वह 'चुराव आयोग' नहीं हो सकता।

बैरिकेडिंग लांघ चर्चा में आए अखिलेश

नई दिल्ली (एजेन्सी)। चुनाव आयोग के विरुद्ध विपक्षी दलों के प्रदर्शन में सोमवार को अखिलेश यादव ने अपनी अलग छाप छोड़ी। सुरक्षाकर्मियों को छकाते हुए पुलिस बैरिकेडिंग लांघने की उनकी तस्वीर पूरे दिन भर मीडिया में छाई रही। अखिलेश यादव की यह तस्वीर उन लोगों को हैरत में डालने वाली थी जो यह मानकर चलते थे कि विरासत में मिली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सड़क की राजनीति में कहीं नहीं टिकते हैं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के विरुद्ध धरने में जिस जीवटता का प्रदर्शन किया है, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सपा को इसका लाभ मिल सकता है। अखिलेश यादव यह जानते हैं कि बिहार के बाद भाजपा सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश पर ही देगी। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि चरणबद्ध तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में चलाई जाएगी। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बिहार-प. बंगाल के बाद यूपी में एसआईआर कराने की शुरूआत कर सकता है। चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि यदि यूपी में भी एसआईआर शुरू होता है तो वे एक बार फिर दलितों-पिछड़ों का वोट काटे जाने का मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति को मजबूत करने की रणनीति अपना सकते हैं। यही कारण है कि सोमवार को दिल्ली में प्रदर्शन में अखिलेश यादव ने अपनी जान लगा दी।

सांस्कृतिक गरिमा और संसदीय विरासत का संगम: दिल्ली विस में दो दिवसीय 'ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस' का आयोजन

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 24 और 25 अगस्त 2025 को विधानसभा के ऐतिहासिक भवन में ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उनके जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित भव्य प्रदर्शनी, विशेष डॉक्यूमेंट्री और स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण किया जाएगा।

स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। विशेष स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया जाएगा।

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह होंगे।

गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में देशभर से 32 विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति शामिल होंगे। राज्य अतिथियों के स्वागत और प्रोटोकॉल के लिए दिल्ली सरकार ने 125 अधिकारियों की नियुक्ति की है। सभी राज्यों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरासत से विकास के विजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा ने इस सम्मेलन में न केवल अपने गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है, बल्कि पेपरलेस प्रणाली, सौर ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्यमुखी विषयों को भी शामिल किया है।

सम्मेलन में चार प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं -विट्ठलभाई पटेल की संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में भूमिका, स्वतंत्रता-पूर्व केंद्रीय विधानसभा के नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में योगदान, शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, तथा भारत-लोकतंत्र की जननी। ये सत्र भारत की संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक शासन में तकनीक की प्रासंगिकता पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान करेंगे।

दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण 1912 में हुआ था और यहां से लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। रॉलेट एक्ट का विरोध भी यहीं से शुरू हुआ था, जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। प्रदर्शनी में विट्ठलभाई पटेल के अभिलेखीय दस्तावेज, फोटोग्राफ और सदन की ऐतिहासिक कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रदर्शित होंगे-जिनमें वह दिन भी दर्ज है जब शहीद भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था। डॉक्यूमेंट्री में महात्मा गांधी के सदन में तीन ऐतिहासिक आगमन, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध और पटेल के अध्यक्ष पद संभालने के क्षण भी दिखाए जाएंगे।

अतिथियों के लिए विशेष रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 23 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत रात्रिभोज, 24 अगस्त को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा रात्रिभोज, और 25 अगस्त को राज निवास में उपराज्यपाल द्वारा रात्रिभोज शामिल हैं। प्रत्येक अवसर पर भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

अंत में अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल विट्ठलभाई पटेल की ऐतिहासिक विरासत को याद करेगा, बल्कि भविष्य के संसदीय लोकतंत्र के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय करेगा। यह आयोजन दिल्ली विधानसभा के लिए विरासत और प्रगति का संगम साबित होगा।

बवाना विधानसभा के शाहबाद डेयरी में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बवाना विधानसभा के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने तिरंगा लहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय निवासियों, युवाओं और महिलाओं ने सहभागिता की।

श्री इंद्राज ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा, देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह हमारी सेना के शौर्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दूर में विजय हासिल कर तिरंगे का मान बढ़ाया है।

उन्होंने सभी से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के संकल्प की दिशा में हर घर पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का पर्व गर्व और उत्साह के साथ मनाएं और आजादी के नायको और वीर शहीदों को नमन करें। कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत सभी घरों, संस्थानों और बाजारों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान 'दिल्ली को कूड़े से आजादी-स्वच्छता अभियान' में योगदान का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर सामाजिक संगठनों, स्कूलों, बाजार संघों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी यात्रा में सहयोग और सहभागिता की। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।

■ 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत सभी घरों, संस्थानों और बाजारों में तिरंगा फहराने का आग्रह

सीएम की अध्यक्षता में एचपीपीसी की बैठक का आयोजन

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपये से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की गई है।

बैठक में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपये की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल तथा 20 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए और यदि कोई सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट श्री डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

■ बैठक में लगभग 1763 करोड़ रुपये से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को दी गई मंजूरी

पंजाब में अपने काले शासन की एक भी उपलब्धि बताओ: मुख्यमंत्री की सुखबीर बादल को चुनौती

संजना भारती संवाददाता

संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बादलों पर राज्य को राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को राज्य में अपने काले लंबे शासन की एक भी उपलब्धि गिनाने की चुनौती दी।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर तंज कसते हुए कहा कि बादलों ने राज्य और इसके लोगों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने कारोबार बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि 2007-2017 का समय सूबे का सबसे काला दौर था, जब ट्रांसपोर्ट, केबल, रेत, नशा और अन्य माफिया ने राज्य में अपने पैर पसारे। भगवंत सिंह मान ने अकाली नेता को इस दौरान अपनी सरकार की एक भी उपलब्धि बताने की चुनौती दी और कहा कि अकाली शासन में नशा तेजी से फैला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे उत्साह के साथ पंजाब और इसके लोगों की सेवा कर रही है और इन नेताओं को अब अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के खिलाफ जघन्य अपराधों के जिम्मेदार नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उन्होंने नाभा जेल में बंद एक बड़े नशा तस्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जब ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ रही है तो पारंपरिक पार्टियां उन्हें बचाने में जुटी हुई हैं।

नशे के आरोप में नाभा जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री के समर्थन में खड़े पारंपरिक दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि कांग्रेसी नेता चरनजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैहरा, भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की मिलीभगत को उजागर करता है और सत्ता में रहते समय वे एक-दूसरे के गलत कामों पर पर्दा डालते हैं। भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर उन्हें चुनौती दी कि वे पंजाब के लोगों को स्पष्ट करें कि वे नशा तस्करों के साथ हैं या उनके खिलाफ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने धर्म को भी नहीं बख्शा और अपने निजी हितों के लिए धन लूटा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सांसदों के लिए पर्याप्त आवास की तीव्र कमी को दूर करना और ऊर्ध्वाधर आवास प्रारूप में आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल आवास प्रदान करना है। उद्घाटन के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया, निर्माण कार्य में शामिल श्रमजीवियों से बातचीत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।

इस दौरान मोदी ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ ओर सामान्य केंद्रीय सचिवालय यानी कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया था। आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इन 4 टावर्स के नाम भी बहुत सुंदर हैं। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की चार महान नदियां, जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जन प्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी पर नाम रखा है, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। ऐसे छोटे मन के लोगों के मन की परेशानियां भी दिखेंगी। नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक नमूना फ्लैट देखने का भी मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का मौका भी मिलता रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उनसे मुक्ति मिलेगी।

सम्पादकीय

पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की धमकी...

दक्षिण एशिया में सामरिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक ओर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर के ताजा बयान ने भारत के पूर्वी मोर्चे पर संभावित खतरे का संकेत दिया है तो दूसरी ओर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आने वाले युद्ध को केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि पूरे देश का युद्ध बताया है। दोनों बयान यह स्पष्ट कर रहे हैं अगला टकराव पारंपरिक सीमाओं से परे होगा, यह सैन्य शक्ति, तकनीक, सूचना युद्ध और जन-भागीदारी का सम्मिलित परीक्षण होगा। हम आपको बता दें कि असीम मुनीर ने The Economist को दिए साक्षात्कार और अमेरिकी धरती पर दिए बयानों में साफ कहा-हम पूर्व से शुरू करेंगे। यह बयान भारत-बांग्लादेश गलियारे की ओर इशारा करता है, जहाँ हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद ढाका का रुख पाकिस्तान के प्रति कुछ नरम दिख रहा है। यहां पुराने इस्लामी नेटवर्क और आतंकी चैनलों के फिर से सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा, मुनीर ने न केवल पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक वार की बात की, बल्कि जल युद्ध की धमकी देते हुए कहा, भारत बांध बनाए और हम उसे दस मिसाइलों से उड़ा देंगे। साथ ही, परमाणु हमले की अप्रत्यक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आया, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के ये बयान उस समय आए हैं जब पाकिस्तान-अमेरिका रिश्तों में सुधार देखने को मिला है। अमेरिकी सेंटकॉम के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात और पाकिस्तान को फिर से अमेरिकी रणनीतिक मानचित्र में लाने का दावा, मुनीर के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। महीने भर में दो बार अमेरिका की यात्रा करने के बाद मुनीर जिस तरह परमाणु धमकियां दे रहे हैं और भारत के साथ आधी दुनिया को लेकर डूबने की बात कह रहे हैं उससे अमेरिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखा जाये तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का अमेरिका की धरती से भारत को सीधी परमाणु धमकी देना केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर संकेत है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को भारत-पाकिस्तान के बीच शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नैतिक आधार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर ने न केवल यदि हमारे अस्तित्व पर खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे जैसी उत्तेजक भाषा का प्रयोग किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी जिम्मेदार परमाणु शक्ति की तरह व्यवहार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप के शांति दूत होने का दावा हास्यास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि उनके देश में खड़े होकर ही पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेता ने परमाणु युद्ध की धमकी दी। यह स्थिति अमेरिका की कूटनीतिक साख पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। सवाल उठता है कि क्या वाशिंगटन अपने मेहमानों के कट्टर और आक्रामक भाषणों को महज राजनीतिक बयानबाजी मानकर अनदेखा करता रहेगा? और क्या दुनिया ऐसे शांति प्रयासों को गंभीरता से लेगी, जिनके बीच ही परमाणु युद्ध की आशंका का सार्वजनिक प्रसारण हो रहा हो? मुनीर का यह बयान एक बार फिर याद दिलाता है कि पाकिस्तान की नीति में परमाणु हथियार सिर्फ रक्षा का साधन नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामरिक दबाव का हथियार हैं-और यही वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा, असीम मुनीर का अमेरिका में खड़े होकर भारत को परमाणु धमकी देना केवल सैन्य या कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आर्थिक मंशा भी झलकती है। पाकिस्तान की यह पुरानी रणनीति रही है कि जब भी उसकी आर्थिक हालत चरमरा जाती है, वह भारत के साथ तनाव बढ़ाकर और परमाणु युद्ध की आशंका पैदा करके वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और दाता देशों पर दबाव बनाता है। इस बार भी यही पैटर्न दिखाई देता है-अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु धमकी देकर पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य वित्तीय एजेंसियों को यह संदेश दिया कि अगर उसके भुगतान रोके गए तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

जयंती

विक्रम साराभाई

जन्म–12 अगस्त, 1919, अहमदाबाद; मृत्यु–30 दिसम्बर, 1971, तिरुवनंतपुरम) को भारत के 'अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक' माना जाता है। इनका पूरा नाम 'डॉ. विक्रम अंबालाल साराभाई' था। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश की उपस्थिति दर्ज करा दी। विक्रम साराभाई ने अन्य क्षेत्रों में भी समान रूप से पुरोगामी योगदान दिया। वे अंत तक वस्त्र, औषधीय, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे थे। डॉ. साराभाई एक रचनात्मक वैज्ञानिक, एक सफल और भविष्य द्रष्टा उद्योगपति, सर्वोच्च स्तर के प्रर्वतक, एक महान संस्थान निर्माता, एक भिन्न प्रकार के शिक्षाविद, कला के पारखी, सामाजिक परिवर्तन के उद्यमी, एक अग्रणी प्रबंधन शिक्षक तथा और बहुत कुछ थे।

पुण्यतिथि

भगवतशरण उपाध्याय

जन्मः 1910; मृत्युः 12 अगस्त, 1982) भारतविद् के रूप में देशी-विदेशी अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरीशस में भारत के राजदूत थे। भगवतशरण उपाध्याय का व्यक्तित्व एक पुरातत्त्वज्ञ, इतिहासवेत्ता, संस्कृति मर्मज्ञ, विचारक, निबंधकार, आलोचक और कथाकार के रूप में जाना-माना जाता है। वे बहुज्ञ और विशेषज्ञ दोनों एक साथ थे। उनकी आलोचना सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के समन्वय की विशिष्टता के कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। संस्कृति की सामासिकता को उन्होंने अपने ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा विशिष्ट अर्थ दिए हैं।

कल मिलेंगे

पिंटू-मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं...
गप्पू-यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत...?
पिंटू-पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं...किसके पास छोड़ूं...!!!

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

भारत की नई बुलंद तस्वीरः 'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए!'

भारत के साथ अपने मनमाफिक डील करने में नाकाम रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को ही 'डेड' बताया था। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी इसी निकृष्ट मानसिकता का दबंग अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे दबंग और गतिशील अर्थव्यवस्था करार दिया। जबकि 'सबके बॉस तो हम है' का भाव रखने वाले कुछ देशों को भारत का तेजी से विकास रास नहीं आ रहा है

-कमलेश पांडेय

दुनिया के आर्थिक और सैन्य मंच पर तेजी से कद्दावर बन चुके गुटनिरपेक्ष देश भारत ने रूस को साधकर नम्बर वन अमेरिका और नम्बर टू चीन को रणनीतिक मुश्किल में डालते हुए भींगी बिल्ली बना दिया है। इससे समकालीन विश्व के जी-7, नाटो, जी-20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ग्लोबल साउथ की पूछ-परख बढ़ गई है, क्योंकि इनका अगुवा अब भारत बन चुका है।

जानकार बताते हैं कि अमेरिकी दांवपेंचों और चीनी पैंतरों से आजिज आ चुके इन ग्लोबल साउथ के देशों को भारत की सदाशयी नीतियों से जो नीतिगत राहत और वैश्विक सहयोग मिला है, वह इनकी प्राथमिक जरूरत भी है। चूंकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत सबसे तेज इकॉनमी बन चुका है, मजबूत सैन्य ताकत के रूप में छा चुका है, इसलिए भारत की मुखालफत दुनियावी थानेदारों को भी भारी पड़ सकती है।

यह ठीक है कि सीजफायर और टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दावों-आरोपों का भारत ने अभी तक जो भी जवाब दिया, उसमें भाषा विनम्र और सांकेतिक रखी गई। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गत दिनों जो ठोक-पीटकर जोशीला राजपूती बयान दिया है, इसके कूटनीतिक और राजनीतिक मायने में बिल्कुल अलग और अहम हैं। ऐसा इसलिए कि ट्रंप का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इस बार जवाब ज्यादा सख्त था।

रक्षा मंत्री सिंह के तल्खी भरे बयान यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब भारत अपने राष्ट्रीय, मित्रगत और पड़ोसी हितों से कोई समझौता नही करेगा और जो इस रास्ते में अड़चनें पैदा करने की कोशिश करेगा, या वैसी ताकतों को शह देगा, उससे सख्ती पूर्वक ही निपटा जाएगा। इस बार सीजफायर वाली हड़बड़ाहट भी नहीं दिखाई जाएगी। इसलिए अब कोई भी बातचीत बराबरी के स्तर पर ही होनी चाहिए। वो भी अमेरिका-चीन जैसे देशों के साथ अनिवार्य तौर पर। लिहाजा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने ठीक ही कहा है कि नया भारत शेर की तरह दहाड़ता है। शक्तिशाली नेताओं की आंखों में देखकर बात करता है।

उल्लेखनीय है कि भारत के साथ अपने मनमाफिक डील करने में नाकाम रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को ही 'डेड' बताया था। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी इसी निकृष्ट मानसिकता का दबंग अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे दबंग और गतिशील अर्थव्यवस्था करार दिया। जबकि 'सबके बॉस तो हम है' का भाव रखने वाले कुछ देशों को भारत का तेजी से विकास रास नहीं आ रहा है। समझा जाता है कि भारत से होने वाले आयात पर अमेरिका के 50 प्रतिशत टैक्स लगाए जाने के बाद उनका यह बयान सामने आया है।

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि हमारी चीजें बाहर महंगी हो जाएं। फिर भी कोई ताकत दुनिया की बड़ी शक्ति बनने से भारत को नहीं रोक सकती है। तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो वह हमारे भारत की है। अब भारत ?24000 करोड़ का रक्षा उत्पाद दुनिया को निर्यात कर रहा है। अब हमने भी ठान लिया है कि आतंकियों को उनके धर्म देखकर नहीं, बल्कि उनका कर्म देखकर मारेंगे। जो हमें छेड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं।

यह महज संयोग नहीं कि रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर बात की और भारत की अर्थव्यवस्था के तेज रफ्तार के बारे में संकेत देते हुए साफ कहा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह गति सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की भावना से हासिल की गई है। पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें स्थान से बढ़कर पहले शीर्ष पांच में पहुंच गई है और अब तेजी से शीर्ष चार से शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निशाना साधने के कुछ दिन बाद पीएम की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम ने यहां तक कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के पीछे भारतीय टेक्नॉलजी और मेक इन इंडिया का हाथ था। उसने कुछ ही घण्टों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते ही भारत की जीडीपी ग्रोथ का 2025-26 के लिए अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखा, जबकि दुनिया की बाकी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए यह अनुमान तकरीबन 3 फीसदी ही है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के डेटा बताते हैं कि 2024 में भारत ने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान दिया और अगले 5 साल में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस तरह से कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे शानदार रिकवरी की और दुनियावी युद्धों व वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी वह बढ़त बनाए हुए है।

दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय विकसित अर्थव्यवस्था की हकीकत यह है कि खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर में गुजर रही है। वहां पर ट्रंप की अव्यवहारिक नीतियों के चलते महंगाई दर बढ़ने का डर है, जिससे आर्थिक विकास दर पर बुरा असर होगा। ऐसा अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का भी मानना है। समझा जाता है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण अगर अमेरिका में मंदी के हालात बनते हैं, तो इसका असर दूसरे मुल्कों पर भी होगा।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि ट्रेड और टैरिफ पर ट्रंप का सख्त रुख किसी के लिए भी सही नहीं है। अब तो इसे टैरिफ टेरर या टैरिफ फतवा तक करार दिया जाने लगा है।आखिरकार इस बढ़े टैक्स की कीमत अमेरिकियों को ही चुकानी पड़ेगी। ऐसे में बेहतर है कि समाधान बातचीत से निकाला जाए। लेकिन, वह बातचीत एकतरफा और अपनी मर्जी थोपने वाली नहीं हो सकती। इसलिए अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भारत की एनर्जी संबंधी जरूरतें अमेरिका से बिल्कुल अलग है। इसी तरह, विशाल किसान व पशुपालक आबादी को लेकर भी भारत की कुछ स्वाभाविक चिताएं हैं। लिहाजा किसी भी समझौते में इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

वहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उनका संकेत पीएम मोदी, एचएम शाह और डीएम सिंह के सख्ती भरे फैसलों व बयानों की तरफ था, जिन्होंने रविवार को धूम मचा दिया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर में ठीक ही कहा कि आज दुनिया में जो देश दादागिरी कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास उन्नत तकनीक है। फिर भी उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि, दुनिया झुकती है बस झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी निर्यात बढ़ानी होगी और आयात घटाने होंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था और निर्यात की दर बढ़ेगी, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, जिनके पास अच्छी तकनीक और संसाधन हैं, वही दबदबा दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास भी यह सब होगा, तो हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति दुनिया के कल्याण की सोच रखती है।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की कई समस्याओं का हल विज्ञान और तकनीक है, और यह ज्ञान ही शक्ति है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो हमें निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना होगा। गडकरी ने सुझाव दिया कि शोध संस्थान, आईआईटीज और इंजिनियरिंग कॉलेज देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर शोध करें, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी शोध जरूरी है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

पुतिन की ये शर्तें कहीं ट्रंप का गुस्सा और भड़का ना दें!

देखा जाये तो पुतिन के लिए युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि रूस की सुरक्षा, भू-राजनीतिक प्रभाव और ऐतिहासिक दावेदारी का मामला है। उनकी रणनीति इस धारणा पर टिकी है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन का उद्देश्य सिर्फ युद्धविराम नहीं, बल्कि एक ऐसा समझौता है जो रूस के दीर्घकालिक हितों को सुनिश्चित करे

-नीरज कुमार दुबे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात न केवल कूटनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि इसके वैश्विक असर को लेकर भी अटकलें तेज हैं। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह स्पष्ट बयान-हम अपनी एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे, यह संकेत देता है कि शांति वार्ता की राह आसान नहीं होगी। वहीं पुतिन भी पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, जिससे टकराव की संभावना बनी हुई है।

हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप वर्तमान समय में खुद को शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे दो बड़े उद्देश्य हैं। पहला है-नोबेल शांति पुरस्कार की महत्वाकांक्षा। दरअसल ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का श्रेय लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिकी चुनावी राजनीति में दबदबा बढ़ाना उनका दूसरा उद्देश्य है। दरअसल वह घरेलू मोर्चे पर यह दिखाना चाहते हैं कि वह वैश्विक संकटों को सुलझाने में सक्षम हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण अंत उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन सकता है।

अब सवाल उठता है कि यदि पुतिन ने ट्रंप की बात मानने से इंकार किया तब क्या होगा? देखा जाये तो अगर पुतिन ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकराते हैं, तो ट्रंप का गुस्सा और रणनीतिक प्रतिक्रिया कई रूप ले सकती हैं जैसे-रूस के खिलाफ नए और कठोर प्रतिबंध लागू हो सकते हैं विशेष रूप से बैंकिंग, ऊर्जा निर्यात और रक्षा क्षेत्र में। इसके अलावा, यूक्रेन को उन्नत हथियार, इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक मुहैया कराई जा सकती है। साथ ही रूस को वैश्विक मंचों पर अलग-थलग करने के लिए यूरोपीय संघ, G7 और NATO देशों को और मजबूती से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, रूस को समर्थन देने वाले देशों– खासकर भारत, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन पर भी अधिक आर्थिक/वित्तीय दबाव डाला जा सकता है।

अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता तो ट्रंप के संभावित सख्त कदमों के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। जैसे तेल और गैस के दाम में उछाल आ सकता है जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी वहीं NATO सीमा पर सैनिक तैनाती बढ़ सकती है। इसके अलावा, रूस समर्थक देशों के बीच सामरिक सहयोग और गहरा हो सकता है। साथ ही पुतिन के संभावित जवाब की बात करें तो माना जा सकता है कि यदि ट्रंप दबाव बढ़ाते हैं, तो पुतिन भी ऊर्जा आपूर्ति, साइबर हमलों या एशियाई गठबंधनों के जरिये अमेरिका और उसके सहयोगियों पर पलटवार कर सकते हैं। इसके अलावा, वह यूक्रेन में सैन्य मोर्चा और आक्रामक बना सकते हैं ताकि बातचीत की शर्तें अपने पक्ष में तय करें। लेकिन यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या पुतिन इस युद्ध समाप्त करने को तैयार होंगे, और यदि हां, तो किन शर्तों पर? साथ ही, क्या अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार करेगा?

देखा जाये तो पुतिन के लिए युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि रूस की सुरक्षा, भू-राजनीतिक प्रभाव और ऐतिहासिक दावेदारी का मामला है। उनकी रणनीति इस धारणा पर टिकी है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन का उद्देश्य सिर्फ युद्धविराम नहीं, बल्कि एक ऐसा समझौता है जो रूस के दीर्घकालिक हितों को सुनिश्चित करे। पुतिन युद्ध समाप्ति के लिए जो संभावित शर्तें रखेंगे उनमें माना जा रहा है कि रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्ज़िया, खेरसॉन) पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी संप्रभुता को मान्यता मिले। इसके अलावा, क्रीमिया पर 2014 के अधिग्रहण को भी मान्यता देने की मांग हो सकती है। यह भी शर्त रखी जा सकती है कि यूक्रेन की तटस्थ स्थिति बनी रहे। यूक्रेन को NATO में शामिल नहीं किया जाये और दीर्घकालिक सैन्य तटस्थता बनाए रखी जाये। साथ ही यह भी शर्त हो सकती है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भारी हथियारों की आपूर्ति पर स्थायी प्रतिबंध लगे। रूस अपने खिलाफ लगे प्रतिबंधों में ढील की मांग भी रख सकता है। इसके तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटाना या कम करना शामिल होगा। इसके अलावा, यूक्रेन में रूसी भाषी आबादी के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा और स्वायत्तता की मांग की जा सकती है।

अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा? देखा जाये तो अमेरिका के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तो उस पर सहयोगी देशों का दबाव होगा। यूरोपीय संघ, विशेषकर पूर्वी यूरोप के देश, किसी भी ऐसे समझौते के खिलाफ होंगे जो रूस को कब्जे वाले क्षेत्रों पर स्थायी नियंत्रण दे। इसके अलावा, अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में रूस के प्रति कड़ा रुख दिखाना ट्रंप के लिए जरूरी होगा, खासकर चुनावी वर्ष में। संभावना है कि अमेरिका कुछ शर्तों को आंशिक रूप से मान सकता है। जैसे-यूक्रेन की NATO सदस्यता पर अस्थायी रोक (लेकिन स्थायी प्रतिबंध पर सहमति मुश्किल)। इसके अलावा, कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील (लेकिन तेल-गैस और बैंकिंग प्रतिबंध बरकरार)।

अब सवाल उठता है कि समझौता नहीं होता है तब क्या होगा? मसलन अगर पुतिन की शर्तें अमेरिका के लिए अस्वीकार्य साबित होती हैं, तो वार्ता विफल हो सकती है। इसके नतीजतन यूक्रेन में युद्ध की तीव्रता बढ़ सकती है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को और उन्नत हथियार व वित्तीय मदद दी जा सकती है। रूस का चीन, ईरान और अन्य पश्चिम-विरोधी देशों के साथ गठबंधन गहरा हो सकता है।

बहरहाल, ट्रंप के लिए पुतिन से यह मुलाकात एक कूटनीतिक अवसर है, लेकिन अगर पुतिन अड़ जाते हैं, तो यह शांति पहल जल्दी ही शक्ति प्रदर्शन की जंग में बदल सकती है। इस टकराव के बीच यूक्रेन का रुख सबसे कठिन है-न तो वह जमीन छोड़ने को तैयार है और न ही लंबे युद्ध से पीछे हटने को। आने वाले समय में यह वार्ता सिर्फ यूक्रेन के भविष्य को नहीं, बल्कि अमेरिका-रूस संबंधों और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगी। यह भी सत्य है कि यह वार्ता तभी सफल होगी जब दोनों पक्ष पूर्ण जीत की बजाय व्यावहारिक समझौते पर तैयार हों। पुतिन के लिए युद्ध समाप्ति का मतलब सम्मानजनक और रणनीतिक लाभकारी शर्तें होंगी, जबकि अमेरिका के लिए यह अपने सहयोगियों को संतुष्ट करते हुए शांति का रास्ता निकालना होगा। अगर यह संतुलन नहीं बन पाया, तो यह बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक फोटो-ऑप बनकर रह जाएगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार

हिंदुओं की मॉब लींचिंग का गढ़ बनता जा रहा बांग्लादेश!

(एजेन्सी)।

बांग्लादेश में शेख हसीना शासन के निर्वासन के बाद से ही हिंदुओं पर हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हिंदुओं को पीटे जाने, उनके मकानों और दुकानों को आग लगाने व मंदिरों पर हमले की खबर अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही लगातदार देखने को मिल रही है। आलम ये है कि बांग्लादेश हिंदुओं की मॉब लींचिंग का गढ़ बनता जा रहा है। एक साल में 142 भीड़ के हमलों में 69 मारे गए हैं। इनमें 21 हिंदुओं पर हमले भी शामिल हैं। अब ताजा मामला बांग्लादेश के रंगपुर का है।

बांग्लादेश के रंगपुर जिले में भीड़ ने दो हिंदू नागरिकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान घनीरामपुर गांव के रुपलाल दास और उनके रिश्तेदार प्रदीप दास के रूप में हुई। रुपलाल जूते सिलने का काम करते थे, प्रदीप वैन चलाते थे। घटना के बाद रुपलाल की पत्नी न्याय की गुहार लगा रही हैं, जबकि उनके 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। शनिवार रात 9 बजे तरगंज-काजीहाट मार्ग के बत्ताला इलाके में दोनों को वैन चोरी और बच्चे की चोरी के शक में रोक लिया गया। चूंकि क्षेत्र में हाल ही में एक बच्चे की हत्या और वैन चोरी की वारदात हुई थी। वैन में 4 छोटी बोतलें थीं, उनमें से एक में कथित फॉर्मलिन जैसी गंध आ रही थी। लोगों ने दोनों को बेरहमी से पीटा और बेहोशी की हालत में बांधकर स्कूल मैदान में छोड़ दिया। देर रात पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, तो रुपलाल को मृत घोषित किया गया, प्रदीप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिछले एक साल में बांग्लादेश में 142 भीड़ हमलों में 69 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 अल्पसंख्यक थे। हिंदू समुदाय पर 21 बार भीड़ हमले हुए।

इजराइल को लगेगा एक और झटका, ऑस्ट्रेलिया भी फिलिस्तीन को देगा मान्यता

(एजेन्सी)।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोमवार को घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया एक फि लिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। यह निर्णय, जिसे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की श्रेणी में लाता है जिन्होंने हाल ही में इसी तरह के इरादे व्यक्त किए हैं। अल्बानीज ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया की मान्यता फि लिस्तीनी प्राधिकरण से प्राप्त विशिष्ट आश्वासनों पर निर्भर करती है। इनमें किसी भी फि लिस्तीनी सरकार से हमास को बाहर रखना, गाजा का विसैन्यीकरण और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति ऑस्ट्रेलिया को फिलिस्तीनी प्राधिकरण से प्राप्त प्रतिबद्धताओं पर आधारित है।

यह घोषणा गाजा में मानवीय संकट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के भीतर बढ़ती आलोचना के बीच आई है, जहाँ अधिकारियों ने जारी पीड़ा और भुखमरी पर चिंता व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया योजनाओं की भी निंदा की है। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि "मध्य पूर्व में हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी को समाप्त करने के लिए दो-राज्य समाधान मानवता की सबसे अच्छी आशा है।

ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के दूत ने कहा कि इस कदम से इजराइल की सुरक्षा कमजोर हुई है। अमीर मैमन ने एक्स को पोस्ट किया। फि लिस्तीनी राज्य को मान्यता देकर, ऑस्ट्रेलिया हमास की स्थिति को और मजबूत कर रहा है, जिसे वह एक आतंकवादी संगठन मानता है।

ऑस्ट्रेलियाई ज्यूरी की कार्यकारी परिषद के प्रवक्ता एलेक्स राइवचिन ने एक बयान में कहा, "यह प्रतिबद्धता फि लिस्तीनियों पर उन चीजों को करने के लिए किसी भी तरह के प्रोत्साहन या कूटनीतिक दबाव को हटा देती है जो हमेशा संघर्ष को समाप्त करने के रास्ते में आती रही हैं।

ओलंपिक मेजबानी के लिए आईओसी से निरंतर बातचीत चल रही-मनसुख मांडविया

(एजेन्सी)।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के भावी मेजबान आयोग के साथ निरंतर बातचीत चल रही है। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के एक प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने कहा कि पूरी बोली प्रक्रिया भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) संभाल रहा है।

खेल मंत्री ने निचले सदन में कहा, आईओए ने आईओसी को आशय पत्र सौंप दिया है। बोली अब आईओसी के भावी मेजबान आयोग के साथ निरंतर बातचीत चरण में है। मंत्री ने हालांकि हेयर के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या भारत कई स्थानों पर ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है। हेयर ने पूछा कि क्या प्रस्तावित योजना में भुवनेश्वर में हॉकी, भोपाल में नौकायन, पुणे में कैनोइंग कयाकिंग और मुंबई में क्रिकेट का आयोजन करना शामिल हैं।

मांडविया ने कहा, भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाना भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की जिम्मेदारी है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) विस्तृत चयन प्रक्रिया से गुजरकर ओलंपिक की मेजबानी के अधिकार सौंपती है। भारत ने हालांकि अपनी बोली में किसी शहर का नाम नहीं दिया है लेकिन गुजरात सरकार इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रही है। उसके खेल मंत्री हर्ष संघवी उस भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसने पिछले महीने बोली पर चर्चा करने के लिए लुसाने स्थित आईओसी मुख्यालय का दौरा किया था।

निरंतर बातचीत के चरण में आइओसी मेजबानी के दावेदारों की तैयारी का व्यावहारिक आकलन करती है। आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने फिलहाल मेजबान चयन प्रक्रिया को रोक दिया है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता पूर्व तैराक कोवेंट्री ने कहा कि जून में उनकी पहली कार्यकारी बोर्ड बैठक के दौरान सदस्यों के बीच आम सहमति थी कि प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। इससे पहले भारत की बोली पर फैसला अगले साल होने की उम्मीद थी।

भारत को कतर और तुर्किए जैसे देशों की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोवेंट्री ने जुलाई में कहा था, आईओसी सदस्यों ने भविष्य के मेजबान चयन प्रक्रिया की समीक्षा करने और इस पर रोक लगाने का समर्थन किया है और हम इस पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेंगे। डोपिंग में भारत का खराब रिकॉर्ड आईओसी के लिए एक मुद्दा है, जिसने आईओए से सुधारात्मक उपाय करने को कहा है। आईओसी द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद आईओए ने भारतीय खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए एक पैनल का गठन किया है।

बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्रः आरबीआई गवर्नर

(एजेन्सी)।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वह गुजरात के मेहसाणा जिले के गोजरिया ग्राम पंचायत में वित्तीय समावेश पर आयोजित एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही।

एक निजी बैंक के बचत खातों के लिए जरूरी न्यूनतम शेष राशि बढ़ाने के बारे में पूछने पर मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई ने न्यूनतम शेष राशि तय करने का निर्णय प्रत्येक बैंक पर छोड़ दिया है। कुछ बैंकों ने इसे 10,000 रुपये रखा है, कुछ ने 2,000 रुपये रखा है और कुछ ने (ग्राहकों को) इससे छूट दी है। यह (आरबीआई के) नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अगस्त से नए बचत खाते खोलने वालों के लिए न्यूनतम शेष राशि की सीमा बढ़ा दी है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, बचत बैंक खाते में न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि (एमएबी) पांच गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दी गई है। यह राशि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पांच गुना बढ़ाकर क्रमशः 25,000 रुपये और 10,000 रुपये की गई है।

दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाताधारकों को न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडित नहीं करने का फैसला किया है। मल्होत्रा ने कार्यक्रम में कहा कि नए युग में सफलता के लिए डिजिटल साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पहले कहा जाता था कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज के युग में डिजिटल साक्षरता के लिए भी यही बात लागू होती है।

कपिल शर्मा की बढ़ी सुरक्षा

(एजेन्सी)। मुंबई पुलिस ने हास्य कलाकार और टेलीविजन होस्ट कपिल शर्मा को पिछले महीने कनाडा के सरे में उनके नए खुले कैफे में गोलीबारी की दो घटनाओं के बाद सुरक्षा मुहैया कराई है। ताजा गोलीबारी गुरुवार, 7 अगस्त की सुबह न्यूटन इलाके में हुई। सरे पुलिस ने एक बयान में कहा कि 7 अगस्त, 2025 को लगभग 4:40 बजे, एसपीएस फ्रंटलाइन अधिकारियों ने 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में एक व्यवसाय के बाहर गोलीबारी की सूचना पर कार्रवाई की। हालाँकि पुलिस ने प्रतिष्ठान की पहचान नहीं की है, लेकिन कनाडाई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि निशाना बनाया गया स्थल शर्माज कप्स कैफे था। यह घटना 10 जुलाई, 2025 को इसी स्थान पर हुई एक ऐसी ही गोलीबारी के बाद हुई है। दोनों ही मामलों में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन बार-बार हुए हमलों ने गंभीर सुरक्षा चिंताएँ पैदा कर दी हैं। सरे पुलिस दोनों घटनाओं की जाँच कर रही है, गोलीबारी के बीच संभावित संबंधों और क्षेत्र में किसी व्यापक आपराधिक गतिविधि से इनके जुड़े होने की जाँच कर रही है। अपने लोकप्रिय टेलीविजन शो "द कपिल शर्मा शो" के लिए मशहूर 43 वर्षीय कॉमेडियन ने इस साल की शुरूआत में अपने विदेशी व्यावसायिक उपक्रमों के तहत यह कैफे खोला था। सूत्रों के अनुसार, शर्मा कनाडाई अधिकारियों के संपर्क में हैं और जाँच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह हमला जुलाई के दूसरे हफ़्ते में इसी कैफे में हुई गोलीबारी की घटना के कुछ ही दिन बाद हुआ था, जिसमें कई गोलियाँ चली थीं। पुलिस ने हमले की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कैफे उसी हफ़्ते की शुरूआत में खुला था। उस सुबह कप्स कैफे की एक खिड़की में कम से कम 10 गोलियों के निशान देखे गए, जबकि एक अन्य खिड़की का शीशा टूटा हुआ था।

परंपरागत व गौरवपूर्ण ढंग से होगा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इन्तजार हुसैन

बदायूँ। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परंपरागत व गौरवपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना होंगे।

कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आहूत बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मलीन बस्तियों में विशेष सफाई सफाई अभियान तथा जनपद के नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए वही निर्वाध आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए।

सीडीओ ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सांय 5:30 बजे नगर पालिका परिषद बदायूं में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि 8:30 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में आतिशबाजी का आयोजन तथा रात्रि 9:00 बजे नगर पालिका परिषद बदायूं में कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन प्रात 6:30 बजे प्रभात फेरी व रूट मार्च का आयोजन किया जाएगा तथा प्रातः 7:30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। प्रातः 9:00 बजे शहीद स्मारकों पर माल्यार्पण होगा। प्रातः 10:00 बजे गांधी जन्मशती चिकित्सालय में ध्वजारोहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रातः 11:00 बजे जिला महिला व पुरुष चिकित्सालय में मरीजों को तथा प्रातः 11:30 बजे जिला कारागार में बंदियों को फलों का वितरण होगा। अपराह्न 2:00 बजे राजकीय महाविद्यालय आवास विकास बदायूं में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम डायट परिसर स्थित ऑडिटोरियम में होगा जिसमें मुख्य अतिथि व उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉ0 अरुण कुमार सक्सेना होंगे।

इस अवसर पर एडीएम ई अरुण कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि एवं राष्ट्र गौरव से ओत-प्रोत 'हर घर तिरंगा यात्रा' का शुभारम्भ

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इन्तजार हुसैन

बदायूँ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ डॉ. बृजेश कुमार सिंह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में रिजर्व पुलिस लाइन्स, बदायूँ में अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे 'हर घर तिरंगा' अभियान 2025 को सफल बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के अमर बलिदान को नमन किया गया तथा पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों एवं राष्ट्रधुन की सुमधुर प्रस्तुति दी गई, जिसने पूरे वातावरण को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा यात्रा का भव्य शुभारम्भ किया गया। यह यात्रा राष्ट्रगौरव एवं राष्ट्रप्रेम के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली बच्चे, महिला पुलिस कर्मी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यात्रा के दौरान राष्ट्रध्वज के साथ देशभक्ति के नारे लगाए गए तथा नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि "भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमें न केवल अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रबल बनाना है।"

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके पश्चात सभी प्रतिभागियों ने हर घर तिरंगा अभियान को पूर्ण उत्साह एवं जोश के साथ सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता व जिला पंचायत अक्ष्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव, सी.डी.ओ. केशव कुमार, ए.डी.एम (ई) अरूण कुमार, ए.डी.एम (एफ.आर.) वैभव शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ० कृष्ण कान्त सरोज, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल, पुलिस उपाधीक्षक लाइन डॉ० देवेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नगर रजनीश उपाध्याय सहित अन्य राजपत्रित अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

शाह अल्वी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इन्तजार हुसैन

बदायूँ। इरफान रहम अली अल्वी का मुख्तार अहमद बाबा के नेतृत्व में एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव अली अल्वी ने साथियों के साथ अपने आवास पर स्वागत किया और चित्र भेंट किया राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान रहम अली अल्वी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया और अली अल्वी ने समाज के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी जोर दिया कहा कि अगर समाज में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ पा रहे आप वैसे व्यक्ति की हर संभव मदद करो और समाज को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की तरफ गौर देना चाहिए जब समाज पड़ेगा जभी बढ़ेगा इस मौके पर हाजी अब्दुल कदीर, मेहंदी अल्वी, यासीन अल्वी, फिरोज अल्वी, इस्हाक अल्वी, एहसान अल्वी, शानू अल्वी, शब्बू अल्वी, सोहेब अल्वी, उवेव अल्वी, मेहरूददीन अल्वी वाहिद अल्वी, शान अल्वी, इब्राहीम अल्वी, आसिफ अल्वी, आदि लोग मौजूद रहे।

स्वतंत्रता दिवस से पहले डीजीपी द्वारा आतंकवाद-रोधी रणनीतियों की समीक्षा, राज्यभर में सुरक्षा बढ़ाने और उच्च-स्तरीय नाके लगाने के निर्देश

पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नशा, गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़/अमृतसर/जालंधर/लुधियाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, आगामी स्वतंत्रता दिवस-2025 के शांतिपूर्ण उत्सव को सुनिश्चित करने के मद्देनजर, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने पुलिस बल को मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद-रोधी रणनीतियों की समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने सीमावर्ती राज्य में किसी भी कानून-व्यवस्था के उल्लंघन को रोकने के लिए अंतर-जिला तालमेल, उच्च-स्तरीय नाके और हर समय निगरानी रखने के निर्देश जारी किए।

डीजीपी पंजाब अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस रेंजों झ्र बॉर्डर, जालंधर, लुधियाना और रूपनगर के अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था संबंधी समीक्षा बैठकें और आउटरीच सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए दौरे पर थे। उन्होंने राज्य में चल रही नशा-विरोधी मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध और गैंगस्टरों व संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति की भी समीक्षा की। नशे के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस रवैये की पुष्टि करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने जिला पुलिस प्रमुखों को एनडीपीएस एक्ट को सख्ती, पारदर्शिता और बिना किसी समझौते के लागू करने के निर्देश दिए। युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम की प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने जिला अधिकारियों को राज्य से नशे की जड़ समाप्त करने के लिए इस मुहिम को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत वित्तीय जांच करने और हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क का पदार्फाश करने के निर्देश भी दिए।

आगामी स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने सभी सीपी/एसएसपी को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित कर शांति और सद्भाव बनाए रखने, डोमिनेशन ऑपरेशनों को तेज करने और अन्य रोकथाम व खुफिया उपायों को बढ़ाने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मी किसी भी संभावित खतरे या गतिविधि को रोकने के लिए विशेषकर रात के समय नियमित गश्त और चेकिंग करेंगे। उन्होंने सीपी/एसएसपी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पुलिस नाकों में वृद्धि करने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, हॉटस्पॉट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा। इस दौरान, आउटरीच सत्र के तहत डीजीपी पंजाब ने स्टेशन हाउस ऑफिसरों (एसएचओ) सहित सभी रैंकों के अधिकारियों से सीधे संवाद किया और अंतर-जिला तालमेल को मजबूत करने तथा ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए खुली चर्चा व महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जानकारी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया।

इस बैठक में पुलिस आयुक्त (सीपी) जालंधर रेंज धनप्रीत कौर, सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, सीपी लुधियाना स्वप्न शर्मा, डीआईजी जालंधर रेंज नवीन सिंगला, डीआईजी रूपनगर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी बॉर्डर रेंज नानक सिंह, एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह, एसएसपी गुरदासपुर अदित्य, एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर, एसएसपी जालंधर ग्रामीण हरविंदर सिंह वीरक, एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा, एसएसपी होशियारपुर संदीप मलिक, एसएसपी पठानकोट दिलजिंदर सिंह ढिल्लों, एसएसपी एसबीएस नगर महिताब सिंह, एसएसपी खन्ना डॉ. ज्योति यादव, एसएसपी जगराओं अंकुर गुप्ता, एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना, एसएसपी एसएएस नगर हरमनदीप हंस और एसएसपी फतेहगढ़ साहिब शुभम अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी शामिल थे।

1,00,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में ए.एस.आई. को विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत आज थाना इस्लामाबाद, अमृतसर में तैनात ए.एस.आई. सतनाम सिंह को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह निवासी भाई मंज रोड, अमृतसर से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उसका करीबी दोस्त पारस मेहता एक वित्तीय सलाहकार है, जिसने सुनील कुमार नामक व्यक्ति के पैसे शेयर मार्केट में निवेश किए। बाजार में गिरावट आने से सुनील कुमार को 2,00,000 रुपए का नुकसान हुआ।

इसके बाद, सुनील कुमार ने पारस मेहता को अपने घर बुलाकर उससे चार खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाए और उस से 6,00,000 का हलफनामा भी ले लिया। इसके उपरांत, सुनील कुमार ने थाना इस्लामाबाद में पारस मेहता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पारस मेहता ने भी सुनील कुमार के विरुद्ध कमिश्नरेट अमृतसर में शिकायत दी।

सुनील कुमार द्वारा दी गई शिकायत की जांच के लिए मामला ए.एस.आई. सतनाम सिंह को सौंपा गया। ए.एस.आई. ने पारस मेहता से संपर्क कर बताया कि वह शिकायत उसे मार्क करवा देंगे और मामले के निपटारे के लिए 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की। उन्होंने तत्काल 20,000 रुपए की पहली किस्त देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता अपने दोस्त के सही और उचित काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता था। इस कारण, उसने पारस मेहता के साथ मिलकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट डी.एस.पी., विजीलेंस ब्यूरो यूनिट, अमृतसर को दी।

विजीलेंस ब्यूरो यूनिट, अमृतसर में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद, सरकारी गवाह की मौजूदगी में आरोपी को 20,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ थाना विजीलेंस ब्यूरो, रेंज अमृतसर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 (भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संशोधित) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच जारी है और आरोपी ए.एस.आई. को कल अदालत में पेश किया जाएगा।

हरदीप सिंह मुंडियां ने 504 पटवारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर आम आदमी को सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया कदमः मुंडियां

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पंजाब के निवासियों को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भर्ती किए गए 504 पटवारियों को आज पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

यहां म्यूनिसिपल भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि 18 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर चुके इन पटवारियों को फील्ड में नियमित पटवारी के रूप में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2023 में राजस्व पटवारियों की भर्ती के बाद योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार ज़िले आवंटित किए थे। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को एक साल का प्रशिक्षण पटवार स्कूल में और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि एक साल के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 अस्थायी पटवार स्कूल खोले गए थे। इन स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कानूनगो शिक्षक अनुभवी और सेवानिवृत्त पी.सी.एस. अधिकारियों, ज़िला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और पटवारी और कानूनगो में से रखे गए थे।

उन्होंने बताया कि इन पटवारियों को प्रशिक्षण के दौरान हिसाब-मुसाब, लैंड रिकॉर्ड, पैमाइश, रिकॉर्ड की तैयारी, इलेक्शन, मुरब्बाबंदी, कृषि और कंप्यूटर विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। इन विषयों में से इलेक्शन और कृषि से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इलेक्शन विषय में मुख्य रूप से मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध में जानकारी दी गई। कृषि विषय में खरीफ और रबी की फसलों, कीटनाशकों, खाद और फसलों के बीजों के संबंध में पूरी जानकारी दी गई। आई.एल.एम.एस. (इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम) सॉफ्टवेयर पर इन उम्मीदवारों को व्यावहारिक रूप से जमाबंदी की डेटा एंट्री, इंतकाल दर्ज करना, रोजनामचा, फर्द बद्र आदि का प्रशिक्षण दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए राज्य के सभी पटवारियों को सीमांकन का प्रशिक्षण देने के लिए डी.जी.पी.एस. (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मशीन खरीदी गई है। इस मशीन के माध्यम से सीमांकन करने का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से गिरदावरी करने का प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है। स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि योग्य उम्मीदवारों की विभागीय परीक्षा 26 मई, 2025 से 3 जून, 2025 तक ली गई। इस परीक्षा में कुल 504 उम्मीदवारों ने विभागीय परीक्षा पास की है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र देने के बाद फील्ड में तैनात किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इन पटवारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा उम्मीदवारों की भर्ती आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार-मुक्त समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं को राज्य की सेवा का मौका देने के लिए पटवारियों के अन्य पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार की बुराई को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ताकि लोगों की भलाई के लिए एक पारदर्शी और कार्यकुशल प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त राजस्व श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि नए पटवारियों की भर्ती का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से परेशानी मुक्त सुविधाएं मिल सकें।

वित्त आयुक्त राजस्व श्री वर्मा ने नव-नियुक्त पटवारियों का विभाग में औपचारिक रूप से आज शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले पटवारियों की तैनाती से ईजी जमाबंदी, ईजी रजिस्ट्री जैसे सुधारों को निचले स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।

पंजाब सरकार ने पी.एस.पी.सी.एल. कर्मचारियों की जायज मुख्य मांगों का किया समाधान

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पावरकॉम के हड़ताली कर्मचारियों से अपनी हड़ताल खत्म करने और जनहित, खासकर मौजूदा गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ी मांग को ध्यान में रखते हुए तुरंत काम पर वापस लौटने की अपील की। बिजली मंत्री ने कहा कि घरों, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है, इसलिए हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबी हड़तालों के कारण लाखों उपभोक्ताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार उनके मुद्दों को ईमानदारी से हल करने के लिए प्रयासरत है। पंजाब सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि 10 अगस्त 2025 को स्थानीय पंजाब भवन में पी.एस.पी.सी.एल. प्रशासन और पावरकॉम कर्मचारी संयुक्त मंच व बिजली कर्मचारी एकता मंच के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक के दौरान, पी.एस.पी.सी.एल. प्रशासन ने कर्मचारियों द्वारा रखी गई लगभग सभी मुख्य मांगों को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी।

ई.टी.ओ. ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों में नई पदों का सृजन और मौजूदा रिक्त पदों को भरना, एक्स-ग्रेशिया राशि में वृद्धि करना, अंतिम निर्णय तक दया याचिका वाले मामलों में वसूली रोकना, कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, लंबित भत्ते जारी करना, ग्रिड सब स्टेशन स्टाफ के ओवरटाइम भुगतान से संबंधित बकाया जारी करना और पेंशन में संशोधन से जुड़े कुछ मामले शामिल हैं।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संपर्क करें: 9871221635

विधायक योगेन्द्र राणा के नेतृत्व में भव्य, अनुशासित और जनभागीदारी से परिपूर्ण तिरंगा यात्रा आयोजित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। असंध शहर में सोमवार को विधायक योगेन्द्र राणा के नेतृत्व में भव्य, अनुशासित और जनभागीदारी से परिपूर्ण तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। यह तिरंगा यात्रा नई अनाज मंडी से आरम्भ होकर नानकपुरा चौंक, सालवन चौंक से होते हुए जींद चौंक पहुंची जहां से मुख्य बाजार से होते हुए फव्वारा चौंक व कब्र चौंक से होते हुए पंजाबी धर्मशाला में तिरंगा यात्रा सम्पन्न हुई। तिरंगा यात्रा के आरम्भ में विधायक योगेन्द्र राणा ने सभी को बताया कि सभी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को बनाए रखेंगे और तिरंगे को सम्मान के साथ पकड़ेंगे।

इस गौरवपूर्ण यात्रा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आमजन और काफी संख्या में महिलाओं ने भी बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा शहर में बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित हुई जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर आमजन द्वारा स्वागत किया गया। हाथों में भारत की आन, बान और शान का प्रतीक तिरंगा लिए यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए।

इस अवसर पर विधायक योगेन्द्र राणा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता और गौरव को प्रोत्साहित करती है। यह तिरंगा यात्रा न केवल स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है, बल्कि भारत की एकता, गौरव और सैनिकों के बलिदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस मौके पर असंध विधायक योगेन्द्र राणा ने देश की बहादुर सेना को नमन करते हुए कहा कि आज देश का हर नागरिक उत्साहित है, खुश है और सुरक्षित महसूस कर रहा है। विधायक योगेन्द्र राणा ने तीनों सेनाओं के वीर जांबाजों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि आज विश्व में देश का गौरव बढ़ा है। विधायक योगेन्द्र राणा ने देश के बहादुर सैनिकों को नमन किया।

विधायक योगेन्द्र राणा ने तिरंगे के महत्व को बताते हुए कहा कि यह हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव का प्रतीक है। इसे फहराना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। तिरंगे का सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र और महान देश के नागरिक हैं। इस दौरान विधायक ने वहां उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि सभी को तिरंगे को सम्मान के साथ अपने घरों और कार्यस्थल पर लगाना है।

इस अवसर पर नगरपालिका चेयरपर्सन सुनीता रानी, असंध विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, गुरबख्शीश सिंह, प्रदीप गोयल, सज्जन अत्री, बृजलाल टक्कर, डॉक्टर बूटी राम, यशपाल राणा, विनीत राणा, विनय राणा, अमित राणा व विभिन्न गांवों के सरपंच और अन्य आमजन उपस्थित रहे।

भारत की सेनाओं, नारी शक्ति के पराक्रम और सम्मान में लिखा गाना ऑपरेशन सिंदूर हुआ लांच

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। देश, देश की सेनाओं और नारी शक्ति के सम्मान में लिखा गया गाना सोमवार को करनाल से लांच हुआ। सेवानिवृत जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह द्वारा लिखे गए ऑपरेशन सिंदूर गाने को तिरंगा यात्रा के शुरू होने से पहले इन्द्री के विधायक रामकुमार कश्यप, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीन लाठर ने तिरंगा यात्रा में शामिल सैंकड़ों कार्यकताओं की उपस्थिति में लांच किया।

इस मौके पर तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक अमरनाथ सौदा, जिला प्रभारी भारत भूषण जुआल, महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष मीना काम्बोज, रोहताश काम्बोज सहित भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने संबोधन में विधायक रामकुमार कश्यप और जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर ने कहा कि देश की आन बान और शान, शहीदों के सम्मान, सेनाओं के पराक्रम के दृष्टिगत में पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम भी समूचे जिला करनाल में तिरंगा यात्रा निकाल रहे है। उन्होंने कहा कि आज देश की सेनाओं और नारी शक्ति के पराक्रम को प्रदर्शित और परिभाषित करता सेवानिवृत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह द्वारा लिखा ऑपरेशन सिंदूर नामक गाना भी लांच किया।

बता दें कि सेवानिवृत डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह के व्यक्तित्व और सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं, सर्जिकल स्ट्राइक, हर घर तिरंगा, कोरोना से बचाव, गलवान और तवांग पराक्रम, नया संसद, 48 कोस, चंद्रयान इत्यादि सामयिक विषयों पर दर्जनों गाने लिख और जनहित में लांच करवा चुके है।

सेवानिवृत डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह ने बताया कि काफी समय से देश और समाज हित के गाने और लेख लिख रहे है। मेरा मुख्य उद्देश्य देश और सेवा के लिए कार्य करते रहना है। अब तक विभिन्न सामाजिक और सामायिक विषयों को लेकर दर्जनों गाने लिख और रिकॉर्ड करवाए और जनहित में लांच किए गए है। ऑपरेशन सिंदूर गाने को गायक सुमेरपाल पाल ने गाया है।

विधायक जगमोहन आनंद की अगुवाई में जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में उमड़े आमजन

■ करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर भी हुए यात्रा में शामिल

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद की अगुवाई में सोमवार को करनाल शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए और तिरंगा हाथों में लेकर भारत माता के जयकारों के साथ शहर के अलग-अलग हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर और भाजपा जिला प्रभारी भारत भूषण जुयाल सहित अनेक गणमान्य शामिल हुए।

तिरंगा यात्रा शहर के रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई। इसके उपरांत सदर बाजार होते हुए महर्षि वाल्मीकि चौक पर खत्म हुई। विधायक जगमोहन आनंद ने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए व नेता जी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ी, लोगों का कारवां जुड़ता चला गया। भारत माता के जयघोष के साथ बड़ी संख्या में करनाल शहर के लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान संबोधित करते हुए करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश के नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। यह अभियान देश के नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद दिलाने के लिए शुरू किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करें और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। तिरंगा हमारी आन-बान और शान का प्रतीक है। हमें गर्व से अपने राष्ट्र ध्वज को अपने घरों पर फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा-2025 में बढ़-चढकर हिस्सा लें। अपनी सेल्फी लें और उसे हर-घर तिरंगा की वेबसाइट पर अपलोड भी करें।

इस मौके पर करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को उन माताओं को नमन करना चाहिए, जिन्होंने शहीदों व योद्धाओं को जन्म दिया। ऐसे वीर शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से ऐसे ही वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का मकसद राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान को मजबूत करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वह एक भारत-श्रेष्ठ भारत देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर-घर तिरंगा अभियान ने अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर ने ने कहा कि आजादी के पावन पर्व पर्व आज पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं है यह हमारी अस्मिता हमारी संस्कृति और बलिदानों का प्रतीक है। इसे सलामी देना एक कर्तव्य हैं और उसके मूल्यों को जीना एक सच्चे नागरिक की पहचान है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के संघर्ष की याद दिलाता है। जिन्होने देश को आजाद करने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। इस मौके पर जिला महामंत्री सुभाष कश्यप, मानव पुरी अशोक भंडारी, संकल्प भंडारी, वरिष्ठ भाजपा नेता भगवान दास अघी, जिला मीडिया प्रभारी डा अशोक कुमार, भाजपा नेता, अशोक खुराना, पूर्व जिला महामंत्री सुनील गोयल, शाम बत्रा, मनमीत बावा, गुलशन नारंग, विकास कथुरिया आदि मौजूद रहे।

असंध में हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा मांग पत्र

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। हरियाणा मनरेगा मेट मजदूर संघ ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय असंध के सभागार में सोमवार को एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में खंड असंध इकाई ने अपनी समस्याएं रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा।

बैठक में संघ के प्रधान ने एक-एक कर सभी मेट्स और मजदूरों की समस्याएं सुनीं और सरकार के समक्ष रखकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया।

मांग पत्र में प्रमुख मांगे शामिल थीं-मनरेगा एक्ट 2005 के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, वर्तमान में कई को 2 दिन भी रोजगार नहीं मिल रहा, शेष दिनों का भत्ता दिया जाए।

जिन गांवों में मेट ठीक काम कर रहा है वहां नई भर्ती रोकी जाए। कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं। मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन की जाए। जेई द्वारा मेजरमेंट बुक में हाजिरी घटाकर मजदूरी काटने की प्रथा बंद की जाए। मजदूरों का वेतन समय पर और कर्मचारियों के साथ एक साथ दिया जाए। मासिक वेतन व्यवस्था लागू की जाए ताकि जिम्मेदारी और कामकाज में सुधार हो। कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये का मुआवजा और आश्रित को नौकरी दी जाए। इसके अलावा भी कई अन्य मांगें रखी गईं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सरकार के समक्ष रखने का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर करण सिंह, अमृत लाल बीएफटी, एबीपीओ सुखबीर सिंह, सुनीता मेट चोरकारसा और चौचड़ा, मनरेगा मेट प्रधान गुलाब मेट सालवन, जोगिंद्र अरड़ाना, राजेश इच्छनपुर, सुमन चौचड़ा, मीना गंगाटेहड़ी, करण सिंह, राममेहर मेट रंगरूटीखेड़ा, रमेश जलमाना आदि मेट उपस्थित रहे।

नगर निगम ने जलापूर्ति व सीवरेज के कनेक्शन वैध करवाने को लेकर करीब 8700 नोटिस किए वितरित-डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा है कि जिन व्यक्तियों ने नगर निगम की अनुमति के बिना जलापूर्ति व सीवरेज के अवैध कनेक्शन लिए हैं, वह उन्हें वैध करवा लें। इसके लिए नागरिकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों का समय दिया है। इसके अतिरिक्त अवैध कनेक्शन लेने वाले करीब 8700 लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।

निगमायुक्त ने कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिक निर्धारित फीस व दस्तावेज जमा करवाकर अपने कनेक्शन को वैध करवाएं। इस अवधि के बीत जाने के बाद अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिकों पर नगर निगम सख्त रुख अपनाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 1500 लोगों ने कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिन नागरिकों ने रिहायशी कनेक्शन लिए हुए हैं, परंतु मीटर नहीं लगवाएं हैं, वह भी अपने मीटर जल्दी से लगवा लें। इससे उनकी सालाना बिल राशि आधी हो जाएगी।

यह देने होंगे दस्तावेज-उन्होंने बताया कि जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन के साथ संपत्ति की रजिस्ट्री, मालिक का आधार कार्ड, फोटो, पडोसी का जलापूर्ति व सीवरेज बिल, सम्पत्ति कर बिल तथा परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति संलग्न करके नगर निगम करनाल कार्यालय में फाइल जमा करवानी होगी। इसके साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा।

यह रहेगी कनेक्शन फीस-उन्होंने बताया कि वैध कनेक्शन लेते समय नागरिकों को कनेक्शन फीस देनी होती है। रिहायशी कनेक्शन के लिए जिन नागरिकों की गली या सडक कच्ची है, उनके लिए 7490 रुपये फीस है और जिनकी गली या सडक पक्की है, उनके लिए 11450 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक कनेक्शन में कच्ची गली या सडक के लिए 8040 रुपये तथा पक्की गली या सडक के लिए 12000 हजार रुपये कनेक्शन फीस रखी गई है। इसी फीस में रोड कट चार्जिज भी सम्मिलित हैं।

इन क्षेत्रों में वितरित किए नोटिस-उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में वैध कनेक्शन लेने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें बसंत विहार, पालम कॉलोनी, प्रतीमपुरा कॉलोनी, राजीव पुरम, नई डी.सी. कॉलोनी, एस.पी. कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर, नरेन्द्र कॉलोनी, रोड कॉलोनी, विकास कॉलोनी, पृथ्वी विहार, महावीर कॉलोनी, हकीकत नगर, पाल नगर, संयज कॉलोनी, चम्बा कॉलोनी तथा आनंद कॉलोनी शामिल है।

मीटर अवश्य लगवाएं नागरिक-उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक स्थानों में जिन लोगों ने नगर निगम से कनेक्शन लेकर मीटर लगवाएं हुए हैं, उनका बिल, मीटर रीडिंग के अनुसार या 1440 रुपये सालाना आता है। इसके विपरीत जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाएं हैं, ऐसे लोगों का सालाना बिल 15 हजार रुपये आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी लोग कनेक्शन लेने के पश्चात मीटर अवश्य लगवाएं।

केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर चरणबद्ध तरीके से पौधारोपण कर इसे हरित बनाना लक्ष्य: राव नरबीर सिंह

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

चंडीगढ़। हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरित हरियाणा-हरित गुरुग्राम बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष वन महोत्सव के दौरान प्रदेशभर में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग का प्रयास रहेगा कि पौधारोपण के दौरान परिपक्व पौधे ही लगाए जाएं जो आगामी 5 व-10 वर्षों में पूरे पेड़ का रूप ले लें और सरकार के हरित हरियाणा हरित गुरुग्राम बनाने के लक्ष्य को चरितार्थ कर दे।

राव नरबीर सिंह आज वजीरपुर फर्रुखनगर रोड स्थित केएमपी एक्सप्रेसवे के नजदीक वन विभाग द्वारा आयोजित 76वें जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 135 किलोमीटर लंबा केएमपी एक्सप्रेस वे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है इसको हरित एक्सप्रेस वे बनाना उनका लक्ष्य है। पहले चरण में मानेसर से फर्रुखनगर तक लगभग 16 किलोमीटर की दूरी में कुल एक लाख एक हजार पौधे लगाने की शुरूआत की गई है।

उन्होंने कहा कि देश में 1950 से वन महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। हरियाणा प्रदेश में पूर्व में यह कार्यक्रम कुछ चिह्नित जिलों तक सीमित था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशों के तहत वर्ष 2025 से इसे प्रदेश के सभी 22 जिलों में व्यापक स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में वन क्षेत्र अत्यंत सीमित है, जो चिंता का विषय है। सौभाग्यवश, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली और नवीनतम श्रृंखला शिवालिक हरियाणा से होकर गुजरती हैं, जो प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद 15 सितंबर से क्षेत्र में विकास कार्य पुनः सक्रिय रूप से शुरू होंगे। साथ ही, उन्होंने लोगों से गुरुग्राम में जारी पॉलीथिन मुक्त अभियान में सक्रिय भागीदारी का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक खेजड़ी एवं रोहिड़ा का विमोचन भी किया।

क्लस्टर लेवल प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन

संजना भारती संवाददाता

असन्ध। डीएवी संस्थान द्वारा डीएवी क्लस्टर लेवल स्पोर्टस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी टूर्नामेंट के तहत डीएवी पब्लिक स्कूल चीका में खो-खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डीएवी पब्लिक स्कूल असन्ध के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता का परिचय दिया। अंडर-14 लड़को की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा अंडर-17 लड़को की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपना नाम चमकाया। अंडर-19 लड़कियों की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा अंडर-14 लड़कियों की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

स्कूल पहुंचने पर टीम के खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह मान ने विजेता टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया तथा स्कूल के खेल विभाग के अध्यापकों को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलकूद हमारे शारीरिक व मानसिक विकास में बहुत सहायक हैं तथा इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्कूल के खेल विभाग के अध्यापक साहब सिंह तथा अध्यापिका ममता द्वारा अथक परिश्रम से टीम के खिलाड़ियों की तैयारी करवाई जिसके परिणामस्वरूप टीम के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पोजीशन हासिल की।

भारतीय चुनाव आयोग की ओर से 1 अगस्त से 11 अगस्त 2025 प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षणः दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी की है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक की प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई है।

श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रारूप सूची के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अब तक मतदाताओं से सीधे 10,570 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और 127 आपत्तियों का 7 दिनों के भीतर निपटारा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से 54,432 फॉर्म 6 और घोषणा आवेदन प्राप्त हुए हैं।

नियमों के अनुसार, सभी प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 7 दिनों की समयसीमा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने और निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, नागरिकों और संगठनों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक सटीक, पारदर्शी और समावेशी मतदाता सूची बनाने में मदद करने की अपील की है।

राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की कार्यवाही निंदनीय: शेर प्रताप शेरी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। कांग्रेस नेता शेर प्रताप शेरी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की कार्यवाही को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। करनाल रोड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की लोकतंत्र और आम जनता की मजबूत आवाज हैं, जिन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता शेरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार जनता की समस्याओं और मुद्दों को संसद व सड़कों पर उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बड़ी है जो भाजपा सरकार को असहज कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को बोलने और विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हाल की घटनाएं यह दशार्ती हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कार्यवाही को तुरंत वापस लेने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग की।

इस अवसर पर मुस्लिम सभा ब्लॉक प्रधान सिराजुद्दीन, जाट महासभा ब्लॉक प्रधान ऋषिपाल आर्य, ईश्वर सिंह फफड़ाना, सुनील सैन, पंकज राणा सालवन, वकील अहमद उपस्थित रहे।